आकाशवाणी देहरादून (उत्तराखण्ड)

शुक्रवार 28.11.2025 समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- देहरादून में आज से शुरु होगा विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन; वैश्विक नेता और विशेषज्ञ, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर करेंगे गहन मंथन।
- राज्य में माधो सिंह भंडारी सहकारी सामूहिक खेती योजना से एक हजार 235 एकड़ भूमि फिर से उपजाऊ; 24 समितियों के दो हजार किसान हो रहे लाभान्वित।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से दिव्यांगजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए सख्त कानून लाने पर विचार करने को कहा।
- नाबालिगों में नशा रोकथाम के लिये देहरादून में विशेष रिहैबिलिटेशन केंद्र शुरू किया जाएगा।

विश्व आपदा प्रबंधन

देहरादून में आज से विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में वैश्विक नेता और विशेषज्ञ, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर गहन मंथन करेंगे। यूकोस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि 30 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में आज उद्घाटन सत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि होंगे।

सम्मेलन में उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान, भागीरथ पुरस्कार और युवा महिला वैज्ञानिक पुरस्कार जैसे नए सम्मान शुरू किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य विज्ञान संचार, आपदा प्रबंधन, जलवायु और महिला वैज्ञानिक नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इसी अवसर पर राज्य स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग 2025 भी आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी 13 जिलों की टीमें क्विज, नवाचार प्रदर्शनी, आपदा प्रतिक्रिया और जलवायु समाधान प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। सम्मेलन के दौरान 20 से अधिक कार्यशालाएं, संवाद सत्र और विशेष कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस इस सम्मेलन से निकलने वाले निष्कर्ष, सुझाव और रणनीतिक समाधान न केवल उत्तराखंड, बल्कि सभी हिमालयी राज्यों के लिये मार्गदर्शक, उपयोगी और दूरगाामी प्रभाव वाले सिद्ध होंगे।

सामूहिक खेती/पलायन रोकथाम

माधो सिंह भंडारी सहकारी समूहिक खेती योजना से प्रदेश के बंजर खेत फिर से आबाद हो रहे हैं और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। सहकारिता विभाग की इस योजना के तहत वर्तमान में एक हजार दो सौ पैंतीस एकड़ भूमि पर सामूहिक खेती की जा रही है और प्रदेशभर की 24 सहकारी समितियों से जुड़े करीब दो हजार चार सौ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास और कृषि पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल अनुपयोगी भूमि उपजाऊ बन रही है, बल्कि किसान संगठित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस मॉडल का और विस्तार किया जाएगा, ताकि पलायन प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार बढ़ सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो।

सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में बंजर खेतों की पहचान कर 4 हजार 750 एकड़ जमीन को आबाद करने का लक्ष्य रखा है। चयनित 70 क्लस्टरों में से 24 में सामूहिक खेती शुरू हो चुकी है, जहां स्थानीय संसाधनों और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में मिलेट्स, बेमौसमी सब्जियां, दालें, फल, औषधीय और सुगंधित पौधों के साथ व्यावसायिक फसलें और चारा उत्पादन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री संबोधन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड निवेश और नवाचार का नया केंद्र बन रहा है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को वैश्विक निवेशक सम्मेलन में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग एक लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। केदारखंड और मानसखंड क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, हरिद्वार–ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर और यमुनातीर्थ स्थल के पुनरुद्धार जैसे कार्य जारी हैं। शीतकालीन यात्रा की पहल से बारहों महीने पर्यटन को बढ़ावा मिला है और धार्मिक, साहसिक व वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड की पहचान और मजबूत हुई है। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में जनता की सहभागिता महत्वपूर्ण है और सामूहिक प्रयासों से राज्य नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ेगा।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड बैठक

नोएड़ा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 9वीं रिव्यू कमेटी की बैठक में राज्य के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार यमुना जल आवंटित किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की कमी के कारण फल, सब्जी और अन्य नकदी फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है, जिससे पलायन बढ़ता है। ऐसे में उत्तराखंड को जल उपलब्धता के अनुपात में हिस्सा मिलना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 1994 के समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश को चार दशमलव शून्य–तीन–दो बिलियन क्यूबिक मीटर जल आवंटित किया गया था। वर्ष 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी जल बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी, और केंद्र के हस्तक्षेप के बाद राज्य को मांग से करीब 32 प्रतिशत कम पानी आवंटित हुआ। 2024 में हुई पिछली बैठक में भी उत्तराखंड को शून्य दशमलव तीन–एक–एक बिलियन क्यूबिक मीटर जल मिला था, जबकि यह राज्य की मांग से काफी कम है।

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से दिव्यांगजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने आज केंद्र से दिव्यांगजनों और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों का उपहास करने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को अनुसूचित जाति–अनुसूचित जन जाति अधिनियम की तर्ज पर दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभद्र, आपत्तिजनक और अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की आवश्यकता है।

नशे के खिलाफ़ कार्रवाई

नाबालिगों में बढ़ती नशे की समस्या को देखते हुए राजधानी देहरादून में बच्चों के लिए विशेष रिहैबिलिटेशन केंद्र शुरू किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग को शीघ्र इसकी गाइडलाइन के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस केंद्र का उद्देश्य कम उम्र में नशे की गिरफ्त में आ चुके बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जिला स्तरीय नारकोटिक्स समन्वय समिति की बैठक में राजधानी में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा में यह जानकारी दी।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी मेडिकल स्टोर में 10 दिनों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल स्टोर्स इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। दवा फैक्ट्रियों और मेडिकल स्टोरों की सघन जांच भी जारी रखने को कहा गया।

उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक ड्रग्स टेस्टिंग कराने और प्रत्येक विद्यालय व कॉलेज में एंटी ड्रग्स कमेटी को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए। श्री बंसल ने सभी स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में मानस हेल्पलाइन 1933 और डिस्ट्रिक्ट डी–एडिक्शन सेंटर हेल्पलाइन 9625777399 के पोस्टर लगाने को कहा, ताकि नशे से जुड़े मामलों की तुरंत जानकारी मिल सके।

भीतकालीन यात्रा

भगवान बदरीनाथ के कपाट बंद होने के बाद आदि जगद्गुरु शंकराचार्य की गद्दी सेना के बैंड के साथ कल ज्योतिर्मठ स्थित नृसिंह मंदिर पहुंची। इसके साथ भगवान बदरीनाथ का खजाना और गरुड़ महाराज की डोली भी ज्योतिर्मठ लाई गई। बदरीनाथ के कपाट 25 नवंबर को बंद हुए थे। इसके बाद 26 नवंबर को कुबेर, उधव, गरुड़ महाराज और शंकराचार्य की गद्दी बदरीनाथ से प्रस्थान कर योगध्यान बदरी पांडुकेश्वर पहुंची, जहां कुबेर और उधव की स्थापना हुई। बुधवार सुबह शंकराचार्य की गद्दी और गरुड़ महाराज की डोली ज्योतिर्मठ पहुंची, जहां नृसिंह भगवान और नवदुर्गा की पूजा के बाद गद्दी की स्थापना की गई और खजाना भगवान नृसिंह को सौंपा गया। गद्दी के ज्योतिर्मठ पहुंचने के साथ ही शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो गई है।

स्वच्छता अभियान

हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए चल रहा स्वच्छता अभियान नौवें दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों से लेकर गांवों और कस्बों तक सफाई कार्य किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी विशेष अभियान चलाया गया। बीएचईएल क्षेत्र में चिन्मय डिग्री कॉलेज से सेक्टर–6 तक सफाई की गई। मंगलौर नगरपालिका क्षेत्र, खानपुर की ग्राम पंचायतों, मंडावर–मंगलौर हाईवे और रुड़की–हरिद्वार रोड पर भी सफाई अभियान चलाया गया।

गौरतलब है कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की निरंतर निगरानी कर इसे प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी स्वयं भी चल रही व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं।